

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ख : 3157

06 फ , 2019 प्रश्न त

गुद संबंधी रोगों म वृद्धि

3157. श्र

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

- (क) क्या देश म गुद संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों को संख्या म वृद्धि हो रही है और यह रोग छोटे शहरों और गांवों म भी फैल चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि ऐसे रोगों के लिए नियमित उपचार को आवश्यकता है लेकिन आयुष्मान भारत योजना के अन्तगत शामिल नहीं किए गए किसान, मध्य वर्गीय लोग और श्रमिक डायलिसिस पर प्रति माह 25-30,000 रुपये खच कर रह ह जिससे उनका परिवार प्रभावित हो रहा है और यदि हां, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या दरभंगा, बिहार के सरकारी अस्पताल म गुद संबंधी रोग के लिए उपचार उपलब्ध नहीं है और रोगी निजी अस्पतालों म डायलिसिस पर 2000-2500 रुपये खच करने के लिए मजबूर है और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;
- (घ) क्या सरकार का ऐसे रोगियाकृ, जिनके पास आयुष्मान काड नहीं है, को निशुल्क डायलिसिस को सुविधा प्रदान करने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य त्र (श्री अश्विनी)

(क) से (ङ.): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को " इंडिया हैल्थ ऑफ दि नेशन्स स्टेट्स" रिपोर्ट के अनुसार पुराने गुदा रोग संबंधी डिसेबिलिटी एडजस्टड लाईफ ईअस (डीएएलवाई) दर 1990 से 2016 के बीच 12% बढ़ी है। आईसीएमआर ने भारत के लोगों म गुदा रोग के प्रचलन पर देश के 7 केन्द्रों - दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलाकाता, गुवाहाटी, मुंबई म बहु-केन्द्रित परियोजना अध्ययन किया है। डाटा के शुरूआती रूझानों से विदित होता है कि पहली स्क्रीनिंग पर सीकेडी के सामुदायिक प्रचलन को रज 5.5% से 18.2% है जबकि प्रथम स्क्रीनिंग म औसत प्रचलन 11.4% है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के रूप म जिला अस्पतालों को सहयोग देने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) शुरू किया गया

है। पीएमएनडीपी के तहत सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को निःशुल्क डायलेसिस सेवाएं प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम के तहत बिहार में पीएमएनडीपी का कार्यान्वयन आरंभ नहीं किया गया है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 7 डायलेसिस मशीनों सहित डायलेसिस सेवा उपलब्ध है। किंतु यह रोगियों के लिए भुगतान करने पर उपलब्ध है।
